

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 27 मार्च, 2007


विषय: अवस्थापना मद के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत योजनाओं की अवशेष धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 437/V-श.वि.-05-31(श.वि)/2005 दिनांक 14.9.2005 एवं शासनादेश संख्या 279/V-श.वि.-06-31(श.वि)/2005 दिनांक 10.2.2006 का संदर्भ ग्रहण करे जिनके द्वारा क्रमशः हरबर्टपुर से फतेहपुर घाईपास तक नहर को भूमिगत करना व सड़क निर्माण हेतु 34.34 लाख तथा विकास नगर जल निकासी योजना प्रथम व द्वितीय चरण हेतु 258.10 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या 801/V-श.वि.-06-186(सा.)टी.सी./03 दिनांक 29.3.2006 द्वारा उक्त शासनादेशों के सापेक्ष मात्र क्रमशः रु. 25 लाख एवं रु. 129.05 लाख आहरित किए जाने के निर्देश दिए गये थे। इस प्रकार उपरोक्त शासनादेशों के विरुद्ध क्रमशः रु. 9.34 लाख और रु. 129.05 लाख, कुल रु. 138.39 लाख अवमुक्त किया जाना अवशेष है।

तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त इंगित धनराशि रु. 138.39 लाख (रु. एक करोड़ अड़तीस लाख उन्तालीस हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यदायी संस्था अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
3. उपरोक्त स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु Third Party Quality Checking की व्यवस्था की जायेगी जिस हेतु संबंधित संस्थाओं से अनुबन्ध होने के उपरान्त आवश्यक निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेगे।
4. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकताये पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाए।
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाए, जितना कि स्वीकृत नाम है। स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
7. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एंजेन्सी के अधिशासी अभियंता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।


(निदेशक)
उत्तराखण्ड शासन

क्रमशः...

8. स्वीकृत कार्य कराने समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
9. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
10. जी.पी.डब्ल्यू. फार्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य संपादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
11. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो संबंधित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
12. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
13. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
14. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को संपादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित करे।
15. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो.नि.वि. के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
16. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
17. कार्य पूर्ण होने पर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
18. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
19. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराने समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या :2290/XXVII(2)/2006 दिनांक-22 मार्च, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

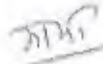
अधी

भवदीय,
(अमरेंद्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या : 254 (1) / V / 2007 तददिनांक ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करें।
9. अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल, देहरादून।
10. अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, विकास नगर।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।



(नाम : जिलाधिकारी)
जिला
नगर विकास
देहरादून

आज्ञा से



(एन. के. जोशी)
अपर सचिव।